



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roc.lko-mef@gov.in, m\_env@rediffmail.com

पत्र सं० ८बी/यू.पी./०६/५४/२०२०/एफ.सी./८३९

दिनांक: 27.08.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण),  
१७, राणा प्रताप मार्ग,  
लखनऊ, ७०८०।

**Online Proposal No. FP/UP/Approach/43673/2019**

विषय: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. लखनऊ द्वारा डलमऊ-ऊँचाहार मार्ग (एस०एच०-३८) के किमी० १८१ (चैनेज सं०-१८० ९३५.९०) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं०-३७८ ग्राम-अलीपुर चकराई, तहसील-डलमऊ, जिला-रायबरेली में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०८१०३ हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-२१७९/११-सी-FP/UP/Approach/43673/2019, दिनांक-१५.०६.२०२०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश, के पत्रांक सं०-२१७९/११-सी-FP/UP/Approach/43673/2019, लखनऊ, दिनांक-१५.०६.२०२० का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

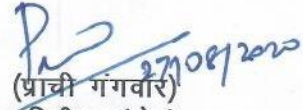
प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-१०.०७.२०२० द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. लखनऊ द्वारा डलमऊ-ऊँचाहार मार्ग (एस०एच०-३८) के किमी० १८१ (चैनेज सं०-१८० ९३५.९०) के मध्य बांयी पटरी पर गाटा सं०-३७८ ग्राम-अलीपुर चकराई, तहसील-डलमऊ, जिला-रायबरेली में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०८१०३ हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in (Compartment/Khasra No. Not provided, Village- Hameermau, Tehsil- Not provided, District- Raibareli) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6. No labour camp shall be established on the forest land.
7. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.



- 8- The separator island will be provided in front of Fuel Station between acceleration and deceleration lanes and the space shall be used for plantation and its boundary shall be demarcated by a 2 ft. wall.
- 9- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
- 10- Greenery will be maintained by the user agency around the periphery of Retail outlet.
- 11- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
17. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

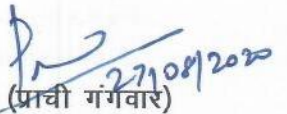
भवदीया,

  
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग), अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग, रायबरेली।
3. जिलाधिकारी, रायबरेली।
4. टेरीटरी मैनेजर (रिटेल सेल्स), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, 94, महात्मा गाँधी, हजरतगंज, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

  
(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक(के०)